

हार के कारणों पर मंथन के लिए भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरु

बैठकों का दौर आज रविवार को भी जारी रहेगा

जयपुर, 15 जून (का.सं.)। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के मिशन 25 को प्रदेश में झटका लगा और पार्टी 14 सीटों पर सिमट गई। राजस्थान के चुनाव परिणाम ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पार्टी के शीर्ष नेताओं की नींद उड़ा दी। अब, प्रदेश में 11 सीटों पर मिली हार को लेकर शनिवार दोपहर से मंथन का दौर शुरु हुआ है जो रविवार को खत्म होगा। इन बैठकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। हालांकि, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भाजपा मुख्यालय में शाम को पहुंचे और चुर लोकसभा सीट को लेकर हो रही बैठक में शामिल हुए। मंथन के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी ने बताया कि, बैठकों में चुनावों के साथ-साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा का रही। आज लोकसभा सीटों पर भी चर्चा हुई, जो कल भी जारी रहेगी।



लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के संदर्भ में भाजपा में बैठकों एवं मंथन का दौर शनिवार को शुरु हुआ। बैठकों भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित हो रही हैं तथा रविवार को भी जारी रहेगी। शनिवार शाम को हुई बैठकों में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जिनमें लोकसभा प्रभारी एवं सांसद प्रत्याशियों सहित तमाम भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की गई।

- बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी व कई अन्य नेता शामिल हुए।
- बैठकों के बाद तैयार रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी।
- बैठक में हरेक लोकसभा सीट का पूरा फीडबैक लिया गया।
- बैठक में डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और कैलाश चौधरी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही।

की समीक्षा की गई। रविवार को भरतपुर, दौसा, गंगानगर सीटों की समीक्षा की करौली-धौलपुर, डूंगरपुर-बांसवाड़ा, जाएगी। इसके आधार पर तैयार रिपोर्ट

केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी के साथ लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी.सी.ए. सह प्रभारी विजया राहटकर मौजूद थीं। बैठक में लोकसभा सीट के बारे में जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, सांसद प्रत्याशी सहित तमाम पदाधिकारियों से चर्चा की गई। एक-एक लोकसभावार पूरा फीडबैक लिया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी नहीं पहुंचे।

पांच सौ वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी पांच साल में

नयी दिल्ली 15 जून (वार्ता) भारतीय रेलवे अगले पांच साल के भीतर 250 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस और 300 से अधिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएगी और देश में रेलवे पटरियों की लंबाई डेढ़ लाख ट्रेक किलोमीटर से अधिक हो जाएगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर संस्करण का ढांचा बन चुका है और अब साजसज्जा की जा रही है। दो माह के भीतर इसके ट्रायल यानी परीक्षण शुरु हो जाएंगे।

- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर संस्करण तैयार हो चुका है, इसके साथ ही देश में रेलवे ट्रेक का विस्तार डेढ़ लाख किलोमीटर तक कर दिया जायेगा।

अगले छह माह के भीतर ये गाड़ी पटरियों पर दौड़ने लगेगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत के मौजूदा चेरकार संस्करण के परिवर्तन के अनुभवों के आधार पर निरंतर सुधार की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत के स्लीपर संस्करण में गुणवत्तापूर्ण का केन्द्र अंचा होने के कारण उसे संतुलित

करने के लिए नीचे के बेस को भारी बनाना जरूरी है। वंदे भारत के स्लीपर संस्करण और चेरकार के नये संस्करण में मोटर की डिजाइन और बोगी की डिजाइन में सुधार किया गया है और मोटर में घूल मिट्टी और पत्थर आने की समस्या का समाधान किया गया है।

‘न मैं स्पीकर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बिहार में एन.डी.ए. जीत भी जाती है तो भी भाजपा को नीतिश कुमार और उनकी पार्टी जद (यू) के साथ में रहना होगा और अपनी सरकार बनाने के लिए अगले पांच साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

हालांकि, नीतीश ने अपनी पार्टी को लिए गए विभागों पर या स्पीकर के पद पर कोई शोर नहीं मचाया है, पर बिहार में शीघ्र चुनाव के लिए उन्होंने लॉबीइंग शुरु कर दी है। समझा जाता है कि उन्होंने अपना मत प्रधानमंत्री मोदी और गुहमंजी अमित शाह के नये संस्करण में मोटर की डिजाइन और बोगी की डिजाइन में सुधार किया गया है और मोटर में घूल मिट्टी और पत्थर आने की समस्या का समाधान किया गया है।

मोदी वाराणसी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निधि केन्द्र सरकार की योजना है जिसका शुभारम्भ 24 फरवरी 2019 को समस्त भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। यह योजना कुछ उच्च आय वर्ग के किसानों को छोड़कर अन्य पर लागू है। उन्होंने कहा कि इस योजना में लाभार्थियों का पंजीकरण करने व उनका सत्यापन करने में पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है और भारत सरकार अब तक इस स्कीम में 3.04 लाख करोड़ रुपये भी वितरित कर चुकी है व अब तक 11 करोड़ किसानों को संपूर्ण देश में इक्का फायदा मिल चुका है और अब जो राशि जारी की जा रही है, उसके बाद जब से यह योजना शुरु की थी।

लाभार्थियों को स्थानान्तरित कुल राशि की रकम 3.24 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीन करोड़ महिलाओं को लक्षित दीदी बनाने का संकल्प लिया, उक्त में एक करोड़ लक्षित दीदीयां पहले ही बनाई जा चुकी हैं, अब 2 करोड़ और बनानी शेष हैं। कृषि सखी उसी का एक आयाम है।

लंग कैंसर सूंघ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इंजीनियरिंग से अस्सिस्टेंट प्रोफेसर देबजित साहा ने बताया कि मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसी ही अद्भुत होती है। साहा व उनकी टीम देखना चाहती थी क्या मधुमक्खी इंसान को सांस में मौजूद रसायनों की पहचान कर सकती हैं, खासकर फेफड़ों कैंसर से पीड़ित व्यक्ति व सामान्य व्यक्ति को सांस में मौजूद रसायनों में अंतर कर सकती है। साहा ने कहा कि मधुमक्खी सांस में मौजूद रसायनों की मात्रा में बेहद मामूली परिवर्तन को भी चिन्हित कर सकती है। यह शोध बायोसेंसस एण्ड बायो इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में छपा है।

मु.मंत्री भजनलाल के 6 माह पूरे, महत्वपूर्ण निर्णय लिया

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी केंद्र के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी

जयपुर, 15 जून (का.सं.)। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी काडर के सेवा नियमों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित) सेवा नियम, 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं (सामान्य पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृत दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक वर्ग के चयन में सुगमता आएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त एवं स्वतंत्र होने से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी काडर के लिए सेवा नियम नहीं बनाये गए, जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं वेतन भत्तों के निर्धारण आदि के कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पा रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने

- इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियम निर्धारित हो सकेंगे और बोर्ड कर्मचारी केंद्र के चयन की राह खुलेगी, इससे बोर्ड को मजबूती मिलेगी।
- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को गठित हुए दस साल हो चुके हैं, पर, अभी तक भी इसके सेवा नियम नहीं बने थे।

विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में वाहन चालकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आठवीं से अपग्रेड करते हुए सैकेंडरी या समकक्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है।

शर्मा के इस निर्णय से भविष्य में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा एवं टेड टेस्ट का आयोजन किया जा सकेगा। इससे सुगम एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुशल वाहन चालकों का चयन किया जा सकेगा।

‘हमारी जीत की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एमवीए महाविकास अघाड़ी के लिए राजनीतिक माहौल बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं।’ अभी हाल ही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनावों में कांग्रेस ने 13 सीटों पर विजय पाई है, ओर प्रदेश में 2019 के मुकाबले संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जबकि शिव सेना (यूबीटी) ने नौ एवं एनसीपी (एसपी) ने आठ सीटों पर जीत दर्ज की है। आम चुनावों के सीट-बंटवारे के समझौते, उद्भव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को तीनों दलों की तुलना में सबसे ज्यादा मिली

थी। लोकसभा की 48 सीटों में से शिव सेना (यूबीटी) ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने 17 सीटों पर तथा एनसीपी (एसपी) ने 10 सीटों पर। यदि तुलना करें तो सत्तारूढ़ महायुति 17 सीटें जीतने में सफल हुई है और भाजपा नीचे गिर कर 23 सीट से 9 पर चुनाव जीती है उसने 2019 में 23 सीटें जीती थी। एकनाथ शिन्दे के नेतृत्ववाली शिव सेना ने कुल 7 सीटें प्राप्त की है, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को इस चुनाव में केवल एक सीट प्राप्त हुई है।

राज्यसभा में और मजबूत होगी एन.डी.ए., 10 सीटों पर चुनाव होंगे

नई दिल्ली, 15 जून। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भले ही फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन अब जो राज्यसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उनमें बड़े फायदे के आसार बन रहे हैं। सांसदों के चुनाव जीतने के कारण राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें एन.डी.ए. को भारी सफलता मिलने की उम्मीद है। ये सभी 10 की 10 सीटें एन.डी.ए. के हिस्से में जाने की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों में एन.डी.ए. की सरकारें हैं। एक और सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र में भी होना है वह

- चुनाववाधीन 10 में से 7 सीटों को भाजपा पुनः हासिल कर लेगी तथा संकेत है कि, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र की तीन सीटें भी भाजपा को मिल सकती हैं।

भी एन.डी.ए. के हिस्से में ही जाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने वाले राज्यसभा के 10 में से सात सांसद भाजपा को हैं। इनमें महाराष्ट्र के उदयन राजे भोसले और पीयूष गोयल, त्रिपुरा में विजय देव, मध्य प्रदेश में ज्योतिराजित्य सिंधिया, बिहार में विवेक ठाकुर, असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्वानंद सोनवाल शामिल हैं। भाजपा एक बार फिर इन सभी सीटों को

सीट पर राज्य में भाजपा की सरकार होने से उसे मिलने की संभावना है, लेकिन राज्य में जिस तरह से जजपा के समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा सरकार निर्दलीय विधायकों के भरसे पर चल रही है, उसे देखते हुए यहां पर चुनाव की स्थिति भी बन सकती है।

महाराष्ट्र की एक और राज्यसभा सीट के उपचुनाव में एन.डी.ए. को ही जीत मिलेगी। यह सीट प्रफुल्ल पटेल के पिछले कार्यकाल के पूरे होने से पहले ही इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी। बाद में प्रफुल्ल पटेल पूरे कार्यकाल वाली सीट से चुनकर राज्यसभा में आए थे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने डीपफेक वीडियोज़ पर लगाम लगायेगी मोदी सरकार

यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे विडियो प्लेटफार्मों को रेगुलेट करने के लिए भी मोदी सरकार आगामी संसदीय सत्र में कड़ा कानून ला सकती है

नई दिल्ली, 15 जून। 2024 लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई मोदी सरकार आने वाले लोकसभा के सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए डीपफेक विडियो और फोटोज पर नजर रखने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की तरफ से लाए जाने वाले इस बिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर तरीकों से इस्तेमाल करने के पर भी ध्यान देने का प्रयास किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस बिल का

नाम डिजिटल इंडिया होगा। सरकार इस बिल को सदन में पेश करने से पहले सभी पार्टियों के साथ इस पर सहमति बनाने का प्रयास करेगी। आगामी लोकसभा सत्र में डीपफेक के अलावा यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे विडियो प्लेटफार्मों को रेगुलेट करने के लिए भी कानून आ सकता है। लोकसभा का अगला सत्र जो कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा। यह 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा, फिर उसके बाद 22 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरु होगा जो कि 9

अगस्त तक चालू रहेगा। इस साल की शुरुआत में केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी इस बिल के बारे में संकेत किया था। चंद्रशेखर ने तब कहा था कि हम इस बारे में सोच रहे हैं और इसको नई सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम चुनाव के पहले इस बिल को लेकर तैयार हो पाएंगे। यह बिल सदन में पेश करने से पहले हमें कई चीजों को देखना होगा, कई मुद्दों पर सलाह लेनी होगी तब जाकर हम इसे सदन में लाने के लिए तैयार हो पाएंगे।

डीपफेक एक टेक्नोलॉजी है जिसने कुछ समय से लगातार लोगों के मन में संदेह पैदा किया है। भ्रमित करने वाला कंटेंट और लोगों कि प्रायवेसी को भंग करने वाली यह टेक्नोलॉजी लगातार सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। लोकसभा चुनावों के पहले चुनाव आयोग ने भी डीपफेक को लेकर अपनी चिंता जताई थी। फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंधाना की एक डीपफेक विडियो वायरल हुई थी जिसके बाद सभी ने इसको लेकर चिंता जताई थी।

कर्नाटक में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब रविवार से पेट्रोल 3 रुपये प्रति लीटर ज्यादा कीमत पर बेचा जाएगा तथा डीज़ल पर अब 3.02 रुपये ज्यादा धुगतान करना होगा। सरकारी सूचना अनुसार प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर कर्नाटक सेल्स टैक्स (के. एस. टी.) 25.92 प्रतिशत से बढ़ाकर 29.84 प्रतिशत कर दिया तथा डीज़ल पर यह वृद्धि 14.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.4 प्रतिशत कर दी है। इस बीच, भाजपा के नेताओं ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा सेल्स टैक्स की दरों में वृद्धि करने के निर्णय की कटु आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया है। केंद्रीय मंत्री बी.एल. शर्मा ने कहा कि कर्नाटक सरकार आम आदमी को बोझ बढ़ाती जा रही है और वो उसके इस बढ़ावतरी की भर्त्सना करते हैं।

अयोध्या के नव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अगर उन्होंने स्पीकर का चुनाव लड़ा तो अयोध्या में भाजपा को हराने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद को चुनाव लड़ाया जाएगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में भाजपा को हराना था, जहाँ भाजपा ने राम मंदिर का भारी प्रचार किया था। दूसरे अवधेश प्रसाद दलित हैं जिससे विपक्ष को मदद मिलेगी।

सूत्रों ने कहा कि स्पीकर का चुनाव लड़कर यह टैस्ट भी हो जाएगा कि विपक्ष के पास कितने वासे हैं। छोटे दल जैसे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, अन्नप्रमुक्त, अकाली दल, बीजू जनता दल आदि एन.डी.ए. में नहीं हैं और इस चुनाव से उनका रुख भी साफ हो जाएगा। और अगर कभी अविश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ा तो इससे विपक्ष को मदद मिलेगी।

इटली की प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी और प्र.मंत्री मोदी की सैल्फी ने खूब सुर्खियां बटोरीं

मोदी ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ सहित दुनिया के कई नेताओं के साथ बातचीत की

नई दिल्ली, 15 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली गए थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बुनिया के शीर्ष नेताओं के बीच उनकी दीवानगी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ सहित दुनिया के कई नेताओं के साथ बातचीत की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ सैल्फी भी ली। इसके अलावा ग्रुप फोटो के दौरान उन्हें मच पर बीच की महत्वपूर्ण जगह दी गई। पीएम मोदी ने शनिवार की सुबह

एक्स पर लिखा, अपुलिया में जी7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही उपयोगी रहा। विश्व नेताओं से बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिससे वैश्विक समुदाय को लाभ हो और भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो। मैं इटली के लोगों और सरकार को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन के साथ भी अलग से बातचीत की। मोदी-बाइडेन की यह बातचीत वाशिंगटन द्वारा सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पट्ट की हत्या की नाकाम साजिश में भारतीय लिंक के आरोपों के करीब सारत महीने बाद हुई है। बाइडेन के साथ अपनी बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका

वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाना इस बात का संकेत है कि तेजी से बढ़ते चीन का मुकाबला करने की पश्चिम की योजनाओं में भारत को प्रमुखता से जगह दी जा रही है। भारत के अलावा 11 विकासशील देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था।